International Initiative for Impact Evaluation

प्रभाव मूल्यांकन सार-संक्षेप

सामाजिक संरक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन

विकास के लक्ष्यों को पूरा करने, प्रमुख रूप से गरीबी घटाने के लिए, दुनिया के कई हिस्सों में समूह-आधारित आजीविका कार्यक्रम लागू किए गए हैं। भारत – एक ऐसा देश जहां पर साझा आर्थिक हित के लिए समूहों के काम करने का लंबा इतिहास है – ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2012 में समान उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की। इस मिशन के दायरे में, क्षमता निर्माण और इसके विस्तार में सहयोग करने के लिए सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (एनआरएलपी) का गठन किया गया।

13 राज्यों के 100 सबसे गरीब जिलों के चुनिंदा ब्लॉकों में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन किया गया, और बाकी बचे हुए जिलों और राज्यों में पहुंचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इस कार्यक्रम की विशिष्टता और ताकत गावों के स्तर पर उच्चतर-क्रम के संगठनों में जमीनी स्तर के एसएचजी के महासंघ – ग्राम संगठनों (वीओ) – और, इसके अलावा, क्लस्टर-स्तर के महासंघों (सीएलएफ) में निहित है। मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए कार्यक्रम को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए एसएचजी सदस्यों का एक 'सामुदायिक कैडर' भी भाग लेता है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर 'मिशन' कहलाने वाली सरकार समर्थित संरचनाएं इन संस्थानों और स्थानीय क्षमताओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

यह संक्षिप्त विवरण 3ie और वृत्ति के शोधकर्ताओं की टीम द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्षों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करता है।

मुख्य झलकियां

- लगभग 5,000 एसएचजी से उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया।
- मूल्यांकन का विस्तार 9 राज्यों और 27,000 उत्तरदाताओं तक रहा।
- उत्तरदाता अत्यधिक ऋणग्रस्तता वाले गरीब ग्रामीण परिवारों से थे। हमने प्रत्येक परिवार से एक वयस्क महिला का साक्षात्कार भी किया।
- कार्यक्रम ने वित्त (फाइनेंस) तक पहुंच बेहतर करके, आय के स्रोतों की संख्या बढ़ाकर और अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम करके परिवारों की आय और बचत में बढ़ोत्तरी की है।
- महिलाओं और पुरुषों दोनों की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ी है।
- कार्यक्रम के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने (एक्सपोजर) का परिवार के औसत खर्च पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा।
- इसमें तब बदलाव आया जब एसएचजी संघबद्ध हुए। एसएचजी का महासंघ गठित होने से कार्यक्रम के फंडों तक बेहतर पहुंच और उनका उपयोग सुनिश्चित हुआ जिससे कार्यक्रम के प्रभाव में सुधार हुआ। वीओ और सीएलएफ ने शिक्षा और उत्पादक परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर ज्यादा खर्च के लिए परिवारों को प्रोत्साहित किया।
- मूल्यांकन ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मापन दो सूचकांकों के माध्यम से किया – उनकी परिवार के 'भीतर' निर्णायक भूमिका, और 'बाहर' सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं के साथ व्यवहार में आत्मविश्वास का स्तर। कार्यक्रम का इन पर कोई उल्लेखनीय समग्र प्रभाव नहीं था।
- महासंघ के रूप में गठित हुए एसएचजी ने महिलाओं के आत्मविश्वास में सुधार दर्शाया, खासतौर पर यदि वे शिक्षित थीं।
- मूल्यांकन के निष्कर्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन की एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:
  - कार्यक्रम एसएचजी सदस्यों को वित्त तक अति आवश्यक पहुंच उपलब्ध कराने में प्रभावी रहा।
  - जैसे-जैसे एसएचजी परिपक्व हुए, वे अधिक फंड तक पहुंच बनाने और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग कर पाने में समर्थ थे।
  - पुराने एसएचजी में सरकारी मानदंडों के अनुपालन के साथ ही ऋणों का एक समान वितरण कम रहा।
  - आरंभिक रोल-आउट चरण को देरी का सामना करना पड़ा, यद्यपि हाल के वर्षों में कार्यान्वयन में सुधार आया है।
  - इससे पता चलता है कि आजीविका संवर्धन हेतु व्यवस्थित निवेशों को सक्षम करने के लिए कार्यक्रम को परिपक्व होना चाहिए।
- एसएचजी और महासंघों (फेडरेशन्स) के बीच क्षमता-निर्माण गतिविधियों की आवश्यकता है।

क्रियाविधि

मूल्यांकन में परिवार स्तर के परिणामों पर डेटा एकत्रित किया गया (एसएचजी सदस्यों और गैर-सदस्यों का सर्वेक्षण करके) और एसएचजी, वीओ, सीएलएफ और ग्राम स्तर पर उत्तरदाताओं के माध्यम से महासंघों के प्रभाव का मापन किया गया। सशक्तीकरण परिणामों की गणना करने के लिए विवाहित महिलाओं को अलग प्रश्नावली उपलब्ध कराई गई। इस मूल्यांकन में इन नौ राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल बिहार- को कवर किया गया।[1] सर्वेक्षण के लिए ग्रामों के प्रतिनिधि नमूने का चयन करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली के डेटा के साथ ब्लॉक अधिकारियों के गहन साक्षात्कार को संयुक्त किया गया।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए किया। आरंभ में, चुनिंदा जिलों में कुछ ब्लॉकों का चयन किया गया; इनके बीच, चुनिदा गांवों में कार्यक्रम लागू किया गया। फिर इसे बाद के चरणों में दूसरे सभी ब्लॉक और गांवों में विस्तारित किया गया। जिन इलाकों में एनआरएलएम को आरंभ में 2011–2012 में लागू किया गया था उन्हें 'आरंभिक ग्राम' (अर्ली विलेजेस) कहा गया और जहां पर आखिर में कार्यान्वयन किया गया (चार या अधिक वर्षों के बाद) उन्हें 'बाद वाले ग्राम' (लेट विलेजेस) का नाम दिया गया।

मूल्यांकन टीम ने परिवार-स्तर के परिणामों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, ब्लॉकों में और ब्लॉकों के भीतर गांवों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय के अंतर का उपयोग करते हुए अंतर-में-अंतर (डिफरेंस-इन-डिफरेंस) क्रियाविधि का उपयोग किया। आरंभिक और बाद में कार्यान्वयन वाले इलाकों के बीच परिणामों में अंतर की तुलना करके प्रभाव की गणना की गई। भौगोलिक इलाकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के आरंभ और चरण के समयों में अंतर से परिणाम प्रभावित न हों इसे सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रणों की व्यवस्था की गई थी।

© McKay Savage / Flickr

निष्कर्ष

नमूने का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

गांव: सर्वेक्षण किए गए गांवों की औपचारिक वित्तीय संस्थाओं और बाजारों तक सीमित पहुंच थी। आधे से भी कम गांवों में गांव (46%) के भीतर किसी बैंक की शाखा थी और एक चौथाई से भी कम गांवों (22%) में कोई मार्केट या बाजार था।

एसएचजी: नमूने में शामिल एसएचजी की औसत आयु चार वर्षों से अधिक (52.2 महीने) थी, जिनमें से अधिकांश वीओ में संघबद्ध हुए थे (79.5%); इन वीओ में से 79% सीएलएफ में संघबद्ध हुए थे। एसएचजी सदस्यों की औसत आयु 38 साल थी जिनकी पढ़ाई-लिखाई मात्र 2.8 साल तक हुई थी।

परिवार: नमूने में शामिल परिवार राष्ट्रीय औसत से अधिक गरीब थे, उनकी आय और बचत कम थी, और ऋणग्रस्तता का स्तर ऊंचा था; राष्ट्रीय औसत क्रमशः 16.6% और 8.6% की तुलना में, 32% परिवार अनुसूचित जातियों और 31% अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे (कुल 63%)।[2] अकुशल श्रम को आय का प्रमुख स्रोत पाया गया, जिसके बाद खेती, वेतनभोगी पेशे और गैर-कृषि उद्यम आते हैं (आकृति 1)।

औसत परिवार का खर्च 1,24,000 रुपये, औसत आय 75,000 रुपये से काफी अधिक था। अधिकांश उत्तरदाताओं (70%) के ऊपर औसत रूप से प्रति परिवार 38,307 रुपये का ऋण था। कई परिवारों के लिए छोटे ऋणों का प्रमुख स्रोत एसएचजी थे, जिन्होंने बड़े ऋणों के अन्य औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तरफ रुख किया (आकृति 2)।

परिवारों के एक बड़े हिस्से (64%) ने तुलनात्मक रूप से छोटी राशि को संस्थागत स्रोतों में बचत करने की जानकारी दी जिसमें बैंक (औसतन 7,100 रुपये), एसएचजी (औसतन 1,712 रुपये) और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं। गरीब परिवार, जो बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने धनी और बेहतर शिक्षित परिवारों की तुलना में अधिक बचत की और कम ऋण लिया।

आकृति 1: परिवार की आय का स्रोत

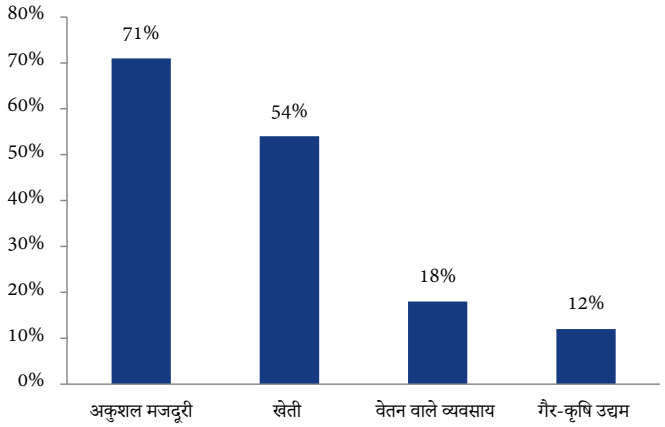

आकृति 2: ऋण का स्रोत

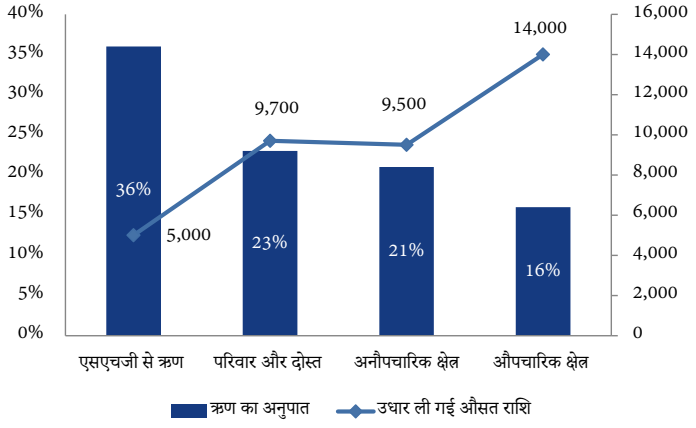

नोट: सीआईएफ = सामुदायिक निवेश फंड; आरएफ = परिक्रामी फंड।

© McKay Savage / Flickr

एसएचजी का कार्यप्रदर्शन

उपलब्ध संसाधनों की एसएचजी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक: एनआरएलएम दिशानिर्देशों के मुताबिक, एसएचजी तीन महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच के हकदार हैं – परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड), सामुदायिक निवेश फंड और बैंक ऋण। यह उपलब्धता उनके गठन के पहले साल के भीतर, कुछ गुणवत्ता मानकों या 'ट्रिगर' के पूरा होने पर पैदा हो जाती है। इन ट्रिगर की उपलब्धि कार्यान्वयन के आरंभिक चरणों में कार्यक्रम स्टाफ द्वारा और एक बार संघबद्ध होने की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद वीओ द्वारा प्रमाणित की गई थी।

फंड प्राप्त करने का मापदंड एनआरएलएम के पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों पंचसूत्र का 90 प्रतिशत से अधिक पालन करने की उपलब्धि है। हमारे विश्लेषण में पाया गया है कि जबकि एसएचजी के एक छोटे से अनुपात ने यह स्कोर हासिल किया, उनकी बड़ी संख्या ने फंड प्राप्त किया, हालांकि देरी से मिला। पांच बिंदुओं के अनुपालन स्कोर पर, पुराने एसएचजी (2014 से पहले गठित) ने सबसे कम स्कोर किया; युवा एसएचजी (2014 के बाद गठित) ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया; और वीओ में संघबद्ध हुए एसएचजी ने सर्वोत्तम प्रदर्शन किया (आकृति 3)।

2012–2013 में गठित आरंभिक एसएचजी ने परिक्रामी फंडों तक पहुंच बनाने में औसतन 30 महीनों का समय लिया, जबकि दिशानिर्देशों में 3 माह निर्धारित थे। यह देरी निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से हुई: एसएचजी के ट्रिगर हासिल करने में विलंब, योग्य एसएचजी के प्रमाणन में विलंब या प्रमाणित एसएचजी को फंड के वितरण में विलंब। हालांकि देर से ही सही, 2017 के सर्वेक्षण के समय आरंभिक एसएचजी के काफी बड़े अनुपात ने फंडों तक पहुंच बना ली थी। 2015 में या उसके बाद गठित हुए एसएचजी के लिए इन आंकड़ों में तेजी से गिरावट आती है (यानी वे जो दो साल पुराने या उससे नए हैं) (आकृति 4)। हालांकि सर्वेक्षण के समय वे बेहतर रहे, लेकिन आरंभिक एसएचजी ने संघबद्ध होने और फंडों तक पहुंच बनाने में काफी लंबा समय लिया।

जबकि एसएचजी के लिए, एक वीओ में संघबद्ध हुए बगैर परिक्रामी और सामुदायिक निवेश फंडों तक पहुंच बनाने के प्रावधान हैं, संघबद्ध हुए एसएचजी की उल्लेखनीय रूप से बड़े हिस्से ने इन फंड तक पहुंच हासिल की। वीओ के आगे सीएलएफ में संघबद्ध होने से परिक्रामी फंड, सामुदायिक निवेश फंड और बैंक ऋणों तक पहुंच का विस्तार हुआ।

आकृति 3: 5 सूत्री पैमाने पर पंचसूत्रों का अनुपालन

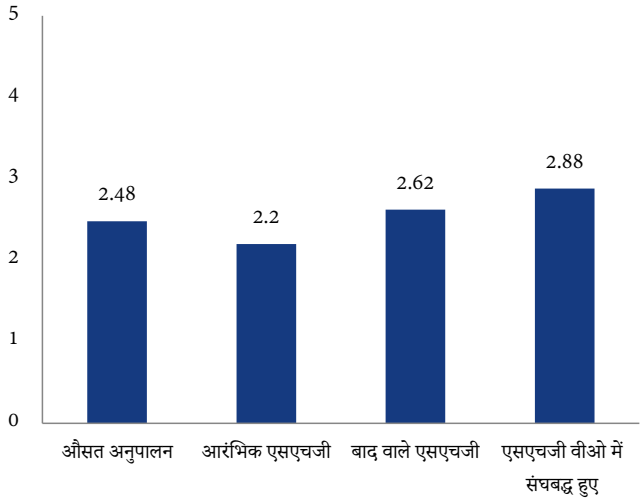

आकृति 4: सर्वेक्षण के समय पहुंचप्राप्त संसाधन

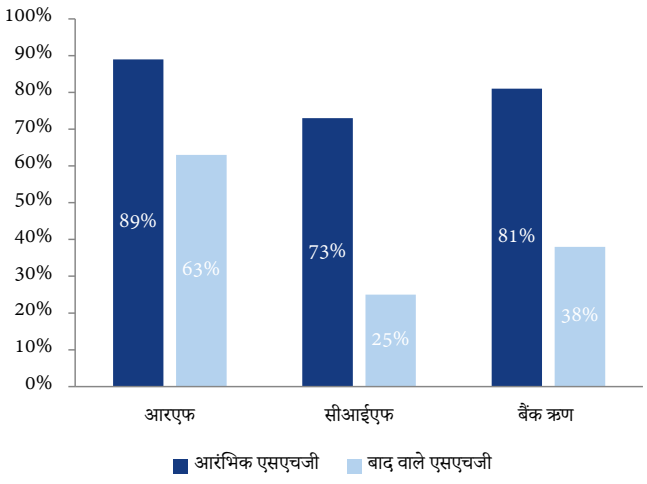

आंतरिक उधारियों को प्रभावित करने वाले कारक – धनराशियां, उपयोग और साम्यता: पुराने एसएचजी ने थोड़े सदस्यों को ज्यादा राशियां ऋण के रूप में दीं। सर्वेक्षण के पहले के 12 महीनों में, युवा एसएचजी ने पुराने एसएचजी की तुलना में 3 गुना तक ज्यादा सदस्यों को ऋण दिए। इसके दूसरी तरफ, पुराने एसएचजी में वितरित ऋणों की औसत राशि (12,824 रुपये) युवा एसएचजी (4,238 रुपये) की तुलना में तीन गुना अधिक थी। आगे के विश्लेषण में पाया गया कि जबकि ऋण की राशि उम्र के साथ बढ़ती है, प्रभाव समय के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है। हालांकि वीओ के रूप में संघ गठित होने के परिणामस्वरूप समय के साथ एसएचजी से ऋण लेने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पुराने एसएचजी के सदस्यों ने उत्पादन और अन्य खर्चों पर अधिक खर्च किया,[3] जबकि युवा एसएचजी के सदस्यों ने उपभोग पर अधिक खर्च किया (आकृति 5)।

युवा एसएचजी ने अधिक साम्यता यानी समान रूप से ऋण उपलब्ध कराए: हालांकि औसत एसएचजी में 11 सदस्य शामिल थे, डेटा दिखाता है कि आमतौर पर दो सदस्यों ने समूह द्वारा वितरित कुल ऋणों का 40% प्राप्त किया – जो कि सबसे कम राशि (14%) प्राप्त करने वाले दो सदस्यों से लगभग तीन गुना था। यह असमानता एसएचजी की उम्र के साथ बढ़ती है, युवा एसएचजी में सबसे कम पंचमांश की 16 प्रतिशत ऋणों तक पहुंच थी, जिसकी तुलना में पुराने में 10 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार, संघबद्ध हुए एसएचजी में असमानता कहीं ऊंचे स्तर पर थी, संघबद्ध न हुए एसएचजी ने निचले पंचमांश को 19 प्रतिशत ऋण दिया, इसकी तुलना में वीओ और सीएलएफ में संघबद्ध एसएचजी में यह 12 प्रतिशत रहा। फिर से, यह तर्कसंगत है कि उम्र और परिसंघ (फेडरेशन) बनने के बीच सहसंबंध दिखा, क्योंकि पुराने एसएचजी के मिलकर परिसंघ या महासंघ बनाने की संभावना अधिक है। कार्यक्रम का समग्र प्रभाव ऋण वितरण में समानता के साथ अधिक फंडों की उपलब्धता पूरी करने पर निर्भर करेगा।

एसएचजी के पास तकनीकी और सामुदायिक कैडर की कमी बनी हुई है: कार्यक्रम ने प्रशिक्षणों के माध्यम से सभी एसएचजी सदस्यों की क्षमता का निर्माण किया है, और परिचालनों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए चुनिंदा सदस्यों को एक 'सामुदायिक कैडर' में पदोन्नत किया है। प्रशिक्षणों की पहुंच का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि केवल कुछ ही (18%) सदस्यों ने एसएचजी के गठन पर निर्धारित मूलभूत अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की जानकारी दी है । इसी प्रकार, सर्वेक्षण किए गए 759 वीओ में कई सामुदायिक कैडर पद रिक्त बने हुए हैं।

आकृति 5: ऋण उपयोग

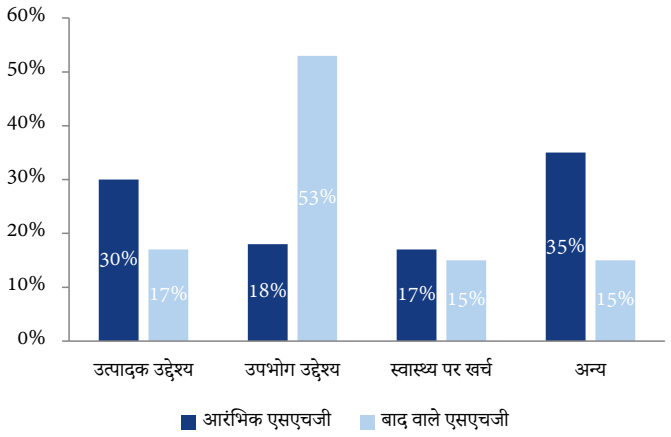

© McKay Savage / Flickr

सम्मिलन (कन्वर्जेंस) को प्रभावित करने वाले कारक – सदस्यों को सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ना: समग्र रूप से, 40% एसएचजी ने सम्मिलन गतिविधियों की सूचना दी है, जिनमें से पुराने एसएचजी ने सर्वोत्तम प्रदर्शन (48%) किया, जो कि युवा एसएचजी (35%) और वीओ में संघबद्ध न हुए एसएचजी (31%) से उल्लेखनीय रूप से आगे थे। वीओ स्तर पर भी, पुरानी संस्थाओं के बड़े अनुपात ने सम्मिलन गतिविधियां शुरू कीं (49%) जिसकी तुलना में सीएलएफ में संघबद्ध न हुए वीओ का आंकड़ा (20%) रहा। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परिसंघ और उम्र सकारात्मक रूप से सम्मिलन की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये गतिविधियां वीओ और सीएलएफ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और पुरानी संस्थाओं के संघबद्ध होने की संभावना अधिक है।

एसएचजी का टिकाऊपन (सस्टेनेबिलिटी): सर्वेक्षण के समय पर, सारे एसएचजी में से 8 प्रतिशत निष्क्रिय थे।[4] युवा (6%) की तुलना में पुराने एसएचजी (10%) में यह दर ऊंची थी। संघबद्ध होने से उनके टिकाऊपन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, वीओ के रूप में संघबद्ध केवल 4 प्रतिशत एसएचजी निष्क्रिय हुए। ऐसे एसएचजी अधिकांश रूप से महाराष्ट्र (18%) और मध्यप्रदेश (29%) राज्यों में संकेंद्रित थे। इन राज्यों के नमूने कुछ सबसे पहले कार्यान्वयन वाले ब्लॉकों से लिए गए हैं, जहां पर संभवतः सदस्यों को पर्याप्त लाभ नहीं मिले, चूंकि कार्यक्रम अपने शुरुआती स्तर पर था। निष्क्रिय एसएचजी 2017 में सर्वेक्षण की तिथि से औसत रूप से 61 महीने पहले गठित हुए थे। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि सदस्यों के पुराने एसएचजी को छोड़ने के शीर्ष कारण मृत्यु (25%) और विस्थापन (21%) थे।

प्रभाव

परिवार के वित्तीय परिणामों – आय, बचत, ऋणों और खर्चों में बदलाव: उन उपचारित ग्रामों के परिवार जहां पर सबसे पहले कार्यक्रम लागू किया गया था, नियंत्रित ग्रामों से अधिक लाभान्वित हुए, जिन्होंने कार्यान्वयन शुरू होने से पहले औसत रूप से 2.5 वर्षों की अवधि तक प्रतीक्षा की। उपचारित परिवारों ने इस अवधि के दौरान आय में औसतन 19 प्रतिशत वृद्धि की सूचना दी। इन परिवारों ने 2.5 वर्षों के दौरान नियंत्रित परिवारों की तुलना में लगभग 17,000 रुपये या मासिक औसतन 570 रुपये की ज्यादा बचत की। यह लाभ एसएचजी खातों में उपचारित परिवारों की नियंत्रित परिवारों की तुलना में 500 रुपये अधिक की बचत या 16 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त में परिवर्तित हुआ।

हालांकि बकाया ऋणों की राशि उपचारित और नियंत्रित क्षेत्रों के लिए एक समान थी, लेकिन जहां पर पुरुष अधिक शिक्षित थे वहां ऋण की राशि ज्यादा थी। इसके अलावा, ऋण लेने के स्रोतों में भी अंतर थे। कार्यक्रम के संपर्क में आने (एक्सपोजर) से उच्च-लागत वाले उन अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता काफी हद तक कम हुई, जिनकी औसत ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिमाह थी। बकाया ऋण वाले सभी परिवारों में से, 32 प्रतिशत कम उपचारित परिवारों ने उच्च-लागत वाले ऋण लेने की सूचना दी।

कार्यक्रम से लंबे समय तक संपर्क में रहने (एक्सपोजर) का औसत परिवार के खर्च पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं था, जिससे परिवार कल्याण के उपायों पर कम प्रभाव का पता चलता है। हालांकि, परिवार खाद्य विविधता सूचकांक में सांख्यिकीय रूप से छोटा लेकिन उल्लेखनीय सुधार रहा और संसाधनों की कमी की वजह से भूखे रहने की शिकायत करने वाले परिवारों के अनुपात में गिरावट आई। वीओ के रूप में संघबद्ध होने का भागीदारी करने वाले परिवारों के स्वामित्व वाली उत्पादक परिसंपत्तियों की संख्या और मूल्य में मजबूत सकारात्मक प्रभाव पाया गया।

महिला सशक्तीकरण में बदलाव: मूल्यांकन में महिलाओं के सशक्तीकरण का मापन करने के लिए दो सूचकांकों का निर्माण किया गया – परिवार के 'भीतर' उनकी निर्णायक भूमिका, और 'बाहर' सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक नेताओं के साथ व्यवहार में उनके आत्मविश्वास का स्तर। कार्यक्रम का इन दोनों सूचकांकों पर कोई उल्लेखनीय समग्र प्रभाव नहीं पाया गया।

हालांकि गहन विश्लेषण ने दर्शाया कि शिक्षा और परिसंघ बनने से 'बाहरी' परिणाम बेहतर हुए। अधिक शिक्षित महिलाओं में पहले से मौजूद उच्च स्तर के आत्मविश्वास में कार्यक्रम के संपर्क में आने के बाद और वृद्धि हुई, जो कि उनके लिए कार्यक्रम के तहत उपलब्ध बेहतर सामुदायिक सहभागिता और नेतृत्व के अवसरों के लिए जिम्मेदार है। परिसंघ (फेडरेशन) ने भी, 'बाहरी' आत्मविश्वास के सूचकांक में सुधार किया है लेकिन उसका 'आंतरिक' निर्णय लेने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं था, जो कि निकटवर्ती रूप से महिला की अपने घरों के भीतर बातचीत की शक्ति से संबंधित था।

© CGIAR Research Program Dryland Systems / Flickr

संस्तुति /अनुशंसा

- अविकसित क्षेत्रों में स्थानीय क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए एसएचजी और महासंघ (फेडरेशन) को निरंतर प्रशिक्षण और संरक्षण प्रदान करें।
- एसएचजी गुणवत्ता का आकलन करने के मौजूदा सूचकांकों का पुनर्मूल्यांकन करें और नेतृत्वकर्ता भूमिकाओं में महिलाओं के चयन के मापदंड का पुनर्मूल्यांकन करें, ताकि ये विकसित क्षेत्रों के एसएचजी और महिलाओं के अनुकूल हों।
- एसएचजी सदस्यों के बीच ऋण वितरण की समानता में सुधार करें।
- गैर-कृषि गतिविधियों पर ध्यान देकर, आजीविका गतिविधियों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करें।
- मूलभूत सामान्य ढांचे का पालन करते समय, एसएचजी को ऐसी गतिविधियां अपनाने के लिए सशक्त बनाएं जो उनके स्थानीय संदर्भ के भीतर व्यवहारिक हैं।

इस सार-संक्षेप के बारे में

इस संक्षिप्त विवरण को हर्ष वर्धन साहनी ने बिदिशा बरुआ के इनपुट के साथ लिखा है। वह सभी सामग्री, त्रुटियों और चूक के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। यह संक्षिप्त विवरण अंजिनी कोचर, बिदिशा बरुआ, चंदन जैन, गीता सिंह, नागभूषण क्लोजपेट, रघुनाथन नारायणन, ऋत्विक सरकार और रोहन शाह की 2020 में प्रकाशित प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट, *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन*, पर आधारित है।

इस मूल्यांकन ने समय-समय पर भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निकाय) से प्राप्त इनपुट, कार्यक्रम की डिजाइनिंग और संचालन में सरकार के साथ विश्व बैंक की तकनीकी भागीदारी से, और इस मूल्यांकन की फंडिंग के लिए बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अत्यधिक लाभ उठाया है।

समाप्ति नोट

[1] जब तक निर्दिष्ट नहीं किया जाए, निष्कर्ष बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सात राज्यों से लिए गए हैं।

[2] महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत, 2011। भारत की जनगणना 2011: प्राथमिक जनगणना सार। नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार। यहां पर उपलब्ध: <https://censusindia.gov.in/DigitalLibrary/Tables.aspx>

[3] इनमें शामिल हैं पुराने ऋण, त्योहार और समारोह, शिक्षा, घरेलू उपयोगी परिसंपत्तियां, घर की मरम्मत और गहने।

[4] वे एसएचजी जो सर्वेक्षण के समय कार्यरत नहीं थे, उन्होंने पूरी तरह सभी परिचालनों को बंद कर दिया।

इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन (3ie) एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदानदाता एनजीओ है जो साक्ष्य आधारित-सूचित विकास नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। हम इसके लिए उच्च-गुणवत्ता वाले साक्ष्य के वित्तपोषण, उत्पादन और संश्लेषण में वैश्विक अगुवा हैं कि क्या कारगर है, किसके लिए, कैसे, क्यों और किस कीमत पर। हमारा मानना है कि बेहतर तथा नीति-संगत साक्ष्य का उपयोग करना विकास को ज्यादा प्रभावी बनाने तथा लोगों की जिंदगियों में सुधार लाने में मददगार है।

3ie के प्रभाव मूल्यांकन पर और अधिक जानकारी के लिए info@3ieimpact.org से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट पर जाएं।

3ieimpact.org

अक्टूबर 2020

@3ieNews /3ieimpact 3ieimpact /company/3ieimpact /3ievideos